उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की सिंचाई योजनाएं

1501. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की कौन कौन सी सिंचाई तथा पेय जल की योजनाएं कब से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना की अलग-अलग लागत कितनी है ; और

(ग) इन योजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रखा दी जाएगी ।

इलाहाबाद तथा वाराणसी टेलीविजन रिले केन्द्रों को शक्तिशाली बनाया जाना

1502. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद तथा वाराणसी टेलीविजन रिले केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल): (क) और (ख) जी, नहीं । इलाहाबाद और वाराणसी दोनों में उच्च शक्ति (10 किलोवाट वाले) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं । इस समय यह देश में लगाए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की उच्चतम शक्ति है ।

Request for import of trawlers by fishery trade owners

1503. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the fishery trade owners has requested Government to import trawlers for deep sea fishing;

(b) if so, the number of trawlers sought to be imported ; and

(c) what is the reaction of Government in the matter in view of the fact that the marine fishing is highly export—oriented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION : (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes Sir.

(b) A number of Indian fishing companies have applied for permission to import 291 deep sea fishing vessels under schemes of general import, charter obligation, 100% Export Oriented Units and Joint Ventures since January 1983 onwards. However, Letters of Permission have been issued only in respect of 64 deep sea fishing vessels so far.

(c) The Government policy towards deep sea fishing is to build up a sizeable fleet of deep sea fishing vessels in order to optimally utilise the available fishery resources in the Exclusive Economic Zone of the Country.

ट्रैक्टरों की आवश्यकता

1504. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के वर्ष के दौरान ट्रैक्टरों का राज्यवार मांग कितनी थी, और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ट्रैक्टरों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी होगी ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के दौरान ट्रैक्टरों की वास्तविक बिक्री का विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)** इस समय ट्रैक्टरों की उपलब्धि में कोई कमी नहीं है, अतः यह मांग को भी दर्शाता है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रैक्टरों की वार्षिक मांग (जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्ताव तैयार करने

के लिए कृतक बल द्वारा मूल्यांकित किया गया है) निम्नवत है :—

वर्ष	अनुमानित वार्षिक मांग
1985 86	92,600
1986-87	1,02,000
1987-88	1,12,000
1988-89	1,23,500
1989-90	1,36,000

विवरण

1985-86 के दौरान ट्रैक्टरों की राज्य-वार बिक्री

क्रम सं.	राज्य	ट्रैक्टरों की बिक्री
1	आन्ध्र प्रदेश	4016
2.	असम	358
3.	बिहार	3512
4.	गुजरात	3972
5.	हरियाणा	9115
6.	हिमाचल प्रदेश	85
7.	जम्मू तथा कश्मीर	68
8.	कर्नाटक	2092
9.	केरल	341
10	मध्य प्रदेश	4966
11	महाराष्ट्र	3504
12.	मणिपुर	7
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	206
16.	पंजाब	13761
17.	राजस्थान	6162
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	2792
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	18135
22.	प. बंगाल	815
23.	संघ राज्य क्षेत्र	100
	अन्य	1006
	योग	75079

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1505. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वर्षों की सेवा के पश्चात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में आवास प्रदान किया जाता है; और

(ख) चालू आबंटन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किस प्राथमिकता तारीख तक सरकारी आवास आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): (क) विभिन्न टाइप के आवासों के लिये लगभग 15 से 29 वर्ष ।

(ख) चालू आबंटन वर्ष के दौरान पूर्ण की जाने वाली सम्भावित अग्रता तिथि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि खाली होने वाले क्वार्टरों की संख्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

परन्तु विद्यमान तारीखें निम्नलिखित हैं :—

टाईप	वर्ष
टाईप-ए	196
टाईप-बी	195
टाईप-सी	196
टाईप-डी	195
टाईप-ई	197

"अकाल राहत कार्यक्रम" के अधीन बांधों की संख्या

1506. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर "अकाल राहत कार्यक्रम" के अन्तर्गत बांधों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या इन बांधों को मानसून के प्रारम्भ से पूर्व पूरा करने की योजना है ;